Frontier Railway, who are drugging passengers for robbing;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps Government are taking to protect the passengers from such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) On 23.7.1991 a raid was conducted by GRP/Guwahati with the assistance of RPF on train No. 2558 Dn. Kanchan Janga Express and a woman, who had drugged two passengers in a coach through sweets, was arrested and on her disclosure, her 8 other associates were arrested.

A criminal case has been registered by GRP/Guwahati.

(c) The maintenance of law and order and control of crime on Railways is the responsibility of the State Government concerned. However, Railways maintain co-ordination with state Government authorities in this connection.

Linking of Godavari and Krishna Rivers

219. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to link Godavari and Krishna rivers, if so, what are the details thereof;

(b) whether there is any proposal from Andhra Pradesh Government pending with Central Government for clearance in this regard; and

(c) if so, at what stage of consideration is pending?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) The Government has prepared a National Perspective for the development of water resources in the country. For the integrated development of Peninsular Rivers, the National Water Development Agency is carrying out water balance studies for the 17 water transfer links. Of these 17 links, the following 3 links involve interlinking of Godavari river with Krishna river:—

(i) Godavari (Polavaram) — Krishna (Vijayawada) link.

(ii) Godavari (Inchampalli)—Krishna (Pulachintala) link.

(iii) Godavari (Inchampalli) — Krishna (Nagarjunasagar) link. National Water Development Agency has studied and prepared preliminary feasibility reports for the first two links.

(b) and (c) The Government of Andhra Pradesh had forwarded a proposal for the construction of Polavaram Project which, inter *alia*, envisaged transfer of water from Godavari to Krishna. Besides, requirement of environment and forest clearances, a number of deficiencies were found in the proposal by the Central Water Commission. Therefore the project was returned to the State Government in 1987.

In July, 1990 the State Government had forwarded updated cost estimate of the project to the Central Water Commission without complying with the deficiencies and observations made in December, 1987. The State Government was requested in July, 1990 itself to furnish a modified project report after compliance of the observations.

Easing of traffic onGrand Trunk Line

220. DR. YALAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to divert either Konark or Godavari Express trains via Nadikude, Guntur in order to ease the traffic on Grand Trunk Line as well as to reduce the distance between Hyderabad and Visakhapatnam and also to facilitate the passengers of Guntur, Nalgonda etc.; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

'नो एलोकेशन फार एस०वाई०एल० प्रोजेक्ट' शीर्षक वाला समाचार

221. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1991 के "ट्रिब्यून" में "नो एलोकेशन फार एस०वाई०एल० प्रोजेक्ट" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने लंबे समय से निर्माणाधीन उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये कोई विशेष कदम उठाने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना की वास्तविक लागत इसकी वर्तमान अनुमानित लागत की तुलना में काफी कम थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये अब कितनी समय वधि निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1991-92 के दौरान कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि इस कार्य के लिये संशोधित अनुमान समय पर प्राप्त नहीं हुये थे। पंजाब सरकार को वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्त तक भारत सरकार द्वारा लंबित अदायगी किये जाने तक उनके अपने संसाधनों से व्यय करने की सलाह दी गई है ।

(ग) पंजाब सरकार को शेष कार्य पूर्ण करने के लिये उपयुक्त अभिकारण/अभिकरणों को लगाने की सलाह दी गई है ।

(घ) परामर्शदात्री समिति द्वारा 1985 में स्वीकृत 272 करोड़ रुपये की परियोजना की लागत की तुलना में 1990 के मूल्य स्तर पर अद्यतन स्वीकृत संशोधित लागत 499 करोड़ रुपये है । लागत में वृद्धि के मुख्य कारण मूल्यों में वृद्धि, संविदाओं पर पंचाट-निर्णय, कार्य के दायरे में वृद्धि और 1988 की बाढ़ों की क्षतियों के कारण किये गये अनिवार्य उपचारी उपायों के कारण हैं । इन्हें पूर्ण करने का निर्धारित समय नये अभिकारण/अभिकरणों के स्वरूप और उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा जिनको पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया जाएगा ।

पीतमपुरा दिल्ली में आवासीय भखंडों को व्यावसायिक भखंडों के रूप में बदलना

222. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत महीनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कतिपय अधिकारियों ने पीतमपुरा दिल्ली के अनेकों आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में लाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन भूखंडों की कुल संख्या क्या थी और इस प्रकार की अनुमति देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी पिछले एक वर्ष के दौरान भूमि के उपयोग के परिवर्तन की अनुमति दी गयी है ;